

को प्रति प्रेषित करने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया। निर्णय किन पक्षकारान की उपस्थित में पारित किया गया यह भी अंकित नहीं किया गया। अतः अपील अपीलाट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 01.07.2015 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलाट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.07.2015 का है लेकिन अपीलाट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 18.11.2017 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट सं0 01 से 03 योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2015 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलाट खारिज फरमायी जावे।
7. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलाट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते हैं। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्त के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक भगवान्या उर्फ भवाना की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 23.12.2010 वाके ग्राम पालडी का है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष अपील पेश कर आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम पालडी तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है जिसकी खातेदारी भगवान्या उर्फ भवाना पुत्र सेवा जाति कुम्हार निवासी गोपालपुरा तहसील रामगढ पचवारा के नाम थी। जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके चारो पुत्रो कमशः रेवडया, मूल्या, काना, महोदव में से महादेव के पुत्रो ने गलत तथ्यों के आधार पर वारिसान बनकर स्वयं के नाम ग्राम पंचायत निजामपुरा से नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 13.12.2010 तस्दीक करवा लिया जिसे निरस्त फरमाया जाकर अपीलाट के हक में हिस्सानुसार नामान्तरकरण तस्दीक फरमाने के आदेश किये जाने की प्रार्थना की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 01.07.2015 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा को रिमाण्ड किया गया।
8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 13.12.2010 वाके ग्राम पालडी के गुणावगुण पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बगैर तथा अपील के अन्दर मियाद घोषित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाट्स (वर्तमान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.08.2012 को अपील पेश की गई थी जिसमें प्रथम आदेशिका दिनांक 13.09.2013 से दिनांक 9.4.2015 तक पीठासीन अधिकारी के दौरे पर जाना अंकित कर रखा हैं। दिनांक 9.4.2015 की आदेशिका के अनुसार भी पीठासीन अधिकारी के दौरे पर रहना अंकित रकते हुये पत्रावली दिनांक 16.6.2015 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलाट्स) को कोई नोटिस जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ना ही इस संबंध में कोई आदेश पारित किये गये है। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 01.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में ली जाकर अप्रार्थी (वर्तमान अपीलाट्स) को बिना सुने एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा (सेवा राम स्वामी) अपीलाट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर बिना विधिक प्रक्रिया अति. संभागीय अदालत पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट जयपुर है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया को पूर्ण किये बगैर पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2015 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर
जयपुर